



भारतीय समाज में निर्धनता की समस्या

□ प्रियंका सिंह

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोध-छात्रा ने भारतीय समाज में निर्धनता की समस्या पर प्रकाश डाला है। भारतीय समाज की निर्धनता सभी समाजों की एक सार्वभौमिक समस्या है। कुछ समाजों में कम लोग गरीब हैं जबकि कुछ समाजों के लोगों का जीवन इस समस्या से अधिक प्रभावित है। भारत में निर्धनता मुख्य रूप से हमारी परम्परागत सामाजिक संरचना का परिणाम है। इस सामाजिक संरचना में देश की आधी से भी अधिक आबादी की आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित किया जाता रहा, अर्थात् निर्धनता का सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के अभावों से होने के साथ ही 'सापेक्षिक वंचन' से भी है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-3 (2005-06) के अनुसार भारत में 40 फीसदी बच्चे कुपोषित हैं जिनमें से रोजाना पाँच हजार बच्चे मौत के मुँह में समा जाते हैं। दुनियाभर में 15500 बच्चे हर रोज मर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि विश्व में कुल मरने वाले बच्चों के एक-तिहाई भाग में यह बिड़बना तब है जब अन्न गोदामों में सड़ रहा है।

गरीबी या निर्धनता का भुखमरी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। गिलिन एवं गिलिन' ने अपनी पुस्तक— कल्चरल सोशियोलॉजी में लिखा है— “निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचारहीन आय के कारण अपने जीवन स्तर को उतना ऊँचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रह सके और वह तथा उसके आश्रित समाज के स्तर के अनुसार जिसका कि वह सदस्य है, जीवन व्यतीत कर सके।” निर्धनता का सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्ति अपनी मूल-भूत आवश्यकताओं की पूर्ति में भी अक्षमता का अनुभव करें। “डब्लू0डब्लू0 बीवर” के शब्दों में “निर्धनता को रहन-सहन की एक ऐसी दशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें स्वास्थ्य और शारीरिक कुशलता को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। “ए0पी0 बर्नवास’ ने निर्धनता के अर्थ को व्यापक आधार पर स्पष्ट करते हुये लिखा है — “निर्धनता आर्थिक अभाव की स्थिति मात्र नहीं है, यह सामाजिक तथा आर्थिक वंचन भी है।” इन दशाओं में हम स्वस्थ व्यक्तियों, शिक्षित बच्चों, समाजीकृत पुरुष व स्थितियों को नहीं प्राप्त कर सकते जो हमारे

सामाजिक संगठन के क्रमिक विकास में रूचि रखने वाले हों।

निर्धनता न केवल ग्रामीण समाज के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति पर प्रभाव डालती है, बल्कि वह उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण भी बनती है। यदि ग्रामीण लोग, अशिक्षित, अन्धविश्वासी, असंस्कृत हैं तो इसका कारण यही है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुये हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण वे शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल नहीं प्राप्त कर पाते। उन्नतशील सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिये आर्थिक समृद्धि एक मौलिक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। निर्धनता से ग्रामीण लोगों को विटामिनयुक्त भोजन नहीं मिल पाता जिससे उनके शरीर एवं दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता धटती जाती है। गरीबी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है, निम्न सामाजिक प्रस्थिति। गरीब किसान प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। गरीब लोगों में विरोध, विद्रोह एवं

□ शोध-छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध वि०वि०, फैजाबाद, (उ०प्र०) भारत

क्रांति के भाव जागृत करती है। अनेक अध्ययनों से यह बात स्पष्ट होती है कि निर्धनता के कारण ही चोरी, डकैती, संधमारी, रिश्वतखोरी, गबन, मिलावट, वेश्यावृत्ति, आत्महत्या जैसे अपराध ग्रामीण समाजों में होते हैं। निर्धनता के कारण 'गरीब लोग अनेक चिंताओं एवं मानसिक व्याधियों से ग्रसित हो जाता है। जिससे मुक्ति पाने के लिये वह (ग्रामीण) शराब पीने लगता है, हुक्का, गांजा, भाँग, बीड़ी, सिगरेट आदि दुर्व्यसनों में फँस जाता है जिससे निकलना उसके लिये बहुत कठिन हो जाता है।

यह कहा जाता है कि 'भारत एक धनी देश है, जहाँ के निवासी गरीब हैं'। भारतीय परिस्थितियों में यह कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है। भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता अधिक जनसंख्या और व्यक्तियों की कार्यकुशलता होने के बाद भी यहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। अतीत में कभी भारत को भले ही 'सोने की चिड़िया' समझा जाता रहा है, लेकिन मुगल-शासन तथा ब्रिटिश शासन में भारत की आर्थिक साधनों का अत्यधिक शोषण हुआ। आज भारत में निर्धनता की समस्या इतनी गंभीर है कि भारत की जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत भाग निर्धनता की चरम सीमा में रहने को विवश है। निर्धनता के कारण ही आज भारतीय ग्रामीणों के बच्चों का जीवन विघटित हो रहा है, लाखों स्त्रियों को अपना शरीर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है तथा एक बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण का जीवन तरह-तरह की कुण्ठाओं, तनावों और क्लेशों में बीत रहा है।

भारत निश्चित रूप से एक उभरती हुयी अर्थव्यवस्था है। किंतु इस साम्राज्य का निर्माण भूखे पेट के ऊपर हुआ है। न्यूयार्क में गरीबी सम्मेलन (2010) में अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व एकत्र हुआ था। एक बार भारत ने विश्व के 50 प्रतिशत भूखों के साथ चार्ट में बाजी मार ली। विश्व के कुल 95.5 करोड़ भूखों में से 46.7 करोड़ भारत में रह रहे हैं। इससे हर भारतीय को शर्मसार होना चाहिये और खास तौर पर लोकतंत्र के नाम पर

शपथ लेने वालों को। जनता के प्रतिनिधि भूख के बढ़ते प्रकोप से बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिये कि लोकतंत्र में भूख विद्यमान क्यों रहती है? "संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी0010)" के 20-22 सितम्बर 2010 को हुये सम्मेलन में जारी आंकड़ों से साफ हो जाता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी को दूर करने में 'वैश्विक नेतृत्व बुरी तरह विफल रहा है। 'अमर्त्यसेन' ने एक बार कहा था कि— "लोकतंत्र में अकाल नहीं पड़ता" किंतु मुझे इसमें बढ़ाना चाहिये कि निर्धनता लोकतंत्र में हमेशा मौजूद रहती है।

भारतीय ग्रामीण समाज में निर्धनता की समस्या को किसी एक या दो कारणों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, बल्कि अनेक दशाओं के संयुक्त प्रभाव से यह समस्या इतनी तीव्र व विषम हो गयी है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ग्रामीण समाज में निर्धनता की समस्या अन्य समाजों से भिन्न प्रकार की है। इन कारकों में जाति-प्रथा, संयुक्त परिवार, अशिक्षा, कर्मकाण्डों पर अपव्यय, आर्थिक कारणों से खेतों की पिछड़ी हुई दशा, योग्य उत्पादकों की कमी, परिवहन तथा संचार साधनों की कमी, प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक शक्तियों का अपर्याप्त उपभोग तथा जनसंख्यात्मक कारक तथा कुछ वैयक्तिक कारण जैसे— बेकारी, बीमारी, मानसिक रोग, नशाखोरी आदि कारक ग्रामीण समाज में निर्धनता के प्रति उत्तरदायी है। बढ़ती भुखमरी और कुपोषण इस बात के भी द्योतक है कि अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व गरीबी एवं भुखमरी के खिलाफ संघर्ष में ईमानदार नहीं है।

भारत में गरीब और भुखमरी के शिकार लोग नये बाजार का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कम्पनियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से दौड़ रही हैं। बहुत से गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पायी है लेकिन कोल्ड-ड्रिंक्स वहाँ भी बिकते नजर आ जायेंगे। इसमें भी हैरत की बात नहीं है कि आज देश में शौचालयों से अधिक संख्या मोबाइल फोन की हो गयी है। भूख एवं गरीबी का बाजार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है इस कारण कृषि

में उन्नत करना आवश्यक है। इसके लिए भूमि व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। किसानों को अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधाएँ मिलना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कृषि के नये उपकरणों अच्छी खाद और सघन खेती के प्रयोग द्वारा भी खेती में सुधार हो सकता है। मेरा मानना है कि कृषि की दशाओं में सुधार होने से देश की आधी निर्धनता अपने आप समाप्त हो जायेगी।

भारतीय ग्रामीण समाज में निर्धनता का एक प्रमुख कारण 'अति-जनसंख्या' भी है। परिवार-नियोजन का अधिक से अधिक प्रचार करके जनसंख्या को कम किया जा सकता है सामाजिक कानूनों को कठोर बनाना चाहिए जिससे ग्रामीणों में व्याप्त दुर्व्यसनों जैसे— शराबखोरी, गांजा, भांग आदि को नियंत्रित किया जा सके। ग्रामीणों को ऋण की सुविधाएँ देने के साथ ही ऋण मिलने की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सके। वर्तमान व्यवस्था में मुनाफा और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के हाथ में केन्द्रित है, ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे पूँजी एवं सम्पत्ति का समान रूप से वितरण हो तथा किसानों को सस्ते दामों पर वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाएँ। इसके साथ ही ग्रामीण बच्चों को अच्छा शैक्षिक अवसर प्रदान कर सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अन्त में किसानों को प्राकृतिक-आपदाओं जैसे— बाढ़, अनावृष्टि, कीड़े-मकोड़ों के प्रकोप आदि से रक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि भारत सरकार इन सुझावों पर अमल करे तो निश्चित रूप से ग्रामीण निर्धनता को समाप्त करने में सहायता मिले।

भारत में निर्धनता दूर करने के लिए आज केन्द्रीय सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयत्न किये हैं। सरकार ने कृषि के विकास को सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है। इस सम्बन्ध में छोटी व बड़ी सिंचाई की योजनाओं द्वारा ग्रामीणों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे भूमियों जो खेती के योग्य नहीं थे फिर से खेती के योग्य बनाने

का सफल प्रयत्न किया जा रहा है। कृषि उत्पादन के लिये उन्नत खाद व दूसरे उर्वरक पदार्थों का भी सरकार आवश्यकतानुसार वितरण कर रही है। उपर्युक्त प्रयत्नों के बाद भी ग्रामीण समाज की आर्थिक दशा में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इस संदर्भ में भारत में आयोजित 'कामन वेल्थ कान्फ्रेंस' में महासचिव 'एस0एस0 रामफल' ने निर्धनता की समस्या की गम्भीरता को स्पष्ट करते हुये कहा — "भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण देश में जनसंख्या की वृद्धि और राष्ट्रीय आय का असमान वितरण होना है। मंहगाई के फलस्वरूप हमारे रहन-सहन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो सका है। इस प्रकार आज निर्धनता से छुटकारा पाना तभी संभव है जब हम दलबन्दी और व्यक्तिगत दलदल से निकलकर राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च स्थान दें।"

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सुरेका, मृंगालाल, "ग्रामीण भारत", नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 1998, पृ0सं0—40।
2. मुकर्जी, आर0के0, "डायनेमिक्स ऑफ रूरल सोसायटी" राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1946, पृ0सं0—10।
3. फुलर, रिचर्ड, सी0 एण्ड मेरी, रिचर्ड, 'सम आस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रब्लम्स', थामसन प्रेस (इण्डिया), फरीदाबाद, 1941, पृ0—24—32।
4. देशाई, ए0आर0, "भारत ग्रामीण समाज शास्त्र" कृषिक अर्थशास्त्र की भारतीय संस्था, बम्बई, 1959, पृ0सं0 59—62।
5. 'भारत' 1999, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, पृ0सं0 232।
6. बर्नवास, ए0पी0 का लेख, 'निर्धनता और उसके सामाजिक प्रभाव', प्लछन् मै2006 'भारत में सामाजिक समस्याएँ', पृ0—7।
7. दैनिक जागरण, लखनऊ, 14 अक्टूबर, 2010।
